मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | ग्वालियर, मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-182, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में सरकार की प्रतिबद्धता का संकल्प सर्वसम्मति से किया पारित

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। सुशासन, विकास एवं राष्ट्र-कल्याण को समर्पित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के गौरवशाली, ऐतिहासिक एवं असाधारण 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ से अधिक जनता की ओर से मंत्रि-परिषद ने कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्दन करते हुए संकल्प पारित किया। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2047 तक 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित मध्यप्रदेश' के निर्माण के महायज्ञ में, प्रधानमंत्री श्री मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया।



मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक में पारित संकल्प के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लोक सेवा के 25 वर्षों में अनथक एवं अर्हनिश पुरुषार्थ के बल पर केवल संकल्प ही नहीं लिए बल्कि उन्हें सिद्ध करके भी दिखाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानसेवक के रूप में उनका यह कार्यकाल त्याग, समर्पण और लोक-कल्याण का अनुपम उदाहरण है। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि पर मध्यप्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का कोटि-कोटि वंदन, आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विस्तार, आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण, डिजिटल क्रांति, विनिर्माण क्षमता को गति देने तथा देश के गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सर्वांगीण सशक्तिकरण से हर नागरिक के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अविस्मरणीय है।

मंत्रि-परिषद के संकल्प के प्रमुख बिंदु

मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए संकल्प में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र में हुए कार्यों का उल्लेख किया गया है। संकल्प में उल्लेख किया गया कि 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला योजना को अंत्योदय को सार्थक करने वाली योजनाएं बताया गया है। संकल्प में नोटबंदी, जीएसटी, तीन तलाक कानून, तीन नई न्याय संहिताएं और जन-विश्वास अधिनियम का उल्लेख है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन, प्रगति मंच पर परियोजनाओं की समीक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पीएम गति शक्ति भी इसमें शामिल हैं। संकल्प के अनुसार यूपीआई की पहचान देश और दुनिया में बढ़ी है और विश्व के लगभग 40 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और इंडिया एआई मिशन को नई तकनीक और अनुसंधान का आधार बताया गया है। दो लाख से अधिक स्टार्ट-अप युवाओं के उद्यमशीलता के सपनों को साकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना और जन औषधि केंद्रों का उल्लेख है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की दिशा को नारी सशक्तिकरण का प्रयास बताया गया है। संकल्प में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख है। आदित्य से चंद्रयान तक के मिशन, श्रीराम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और एकात्म धाम के कायाकल्प को भी संकल्प में दर्ज किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश, 15 उड़ानों में देरी

एजेन्सी, नई दिल्ली



दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के गरज के साथ तेज बारिश हुई जिससे दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब 15 उड़ानों में देरी की सूचना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने तड़के साढ़े चार बजे के आसपास यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें उड़ानों की ताजा स्थिति की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी है। उसने कहा है कि मौसम विभाग ने एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में खराब मौसम की संभावना जताई है हालांकि ह्फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य हैह्व। दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार, तड़के 4.50 के बाद से करीब 15 उड़ानों में देरी की सूचना है। इनमें अधिकतर आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल और रीवा संभाग में रविवार को बूंदाबांदी हुई। कुछ जगहों पर बादल भी छाए रहे। क्टऊ (मौसम केंद्र) भोपाल के मुताबिक, सोमवार से साइक्लोनिक सकुर्लेशन (चक्रवात) का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद रात में ठंड बढ़ेगी, लेकिन पूरे अक्टूबर दिन में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर से रात में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। इससे पहले बीती रात इंदौर में पारा 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

चावल निर्यातकों का बड़ा मास्टरस्ट्रोक

इराक भेजा 1.02 लाख टन बासमती, 74% घट गई माल ढुलाई लागत

एजेन्सी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक चुनौतियों, कंटेनरों की किल्लत और बढ़ती माल ढुलाई लागत से जूझ रहे भारतीय चावल निर्यातकों ने एक बड़ा कारोबारी दांव खेला है। भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) ने सिंगापुर स्थित एक्सिमवाला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इराक को 1,02,210 टन बासमती चावल भेजने के लिए तीन बड़े मालवाहक जहाजों का विशेष प्रबंध किया है। इस रणनीतिक कदम से माल ढुलाई की



लागत 350 डॉलर प्रति टन से घटकर सीधे करीब 90 डॉलर प्रति टन पर आ गई है। प्रति टन लगभग 260 डॉलर की इस भारी बचत से भारतीय निर्यातकों को कुल 2.66 करोड़ डॉलर (लगभग ?223 करोड़) की सकल राहत मिलने का अनुमान है।

जहाजों के जरिए इराक चावल भेजने का पूरा लॉजिस्टिक प्लान क्या है?

पश्चिम एशिया के साथ व्यापार में जहाजरानी की बाधाओं और ऊंची लॉजिस्टिक लागत को दूर करने के लिए भारतीय निर्यातक संघ ने सामान्य कंटेनर परिवहन के बजाय बड़े मालवाहक जहाजों का रुख किया है। यह पूरी खेप इराक के उम्म कसर बंदरगाह पर उतारी जा रही है।

विपक्ष का पहली बार सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल



एजेन्सी, नई दिल्ली

SIR में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पार्टी बनाया गया है।

इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। यह पहली बार है जब विपक्षी नेताओं ने किसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। करीब एक किमी लंबे मार्च में विपक्ष के नेता बस में, पैदल और वाहन में सवार हुए।

मार्च के पहले राहुल गांधी ने 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। रविवार को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया था और याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

पटाखा बैनः सुप्रीम कोर्ट बोला-कम प्रदूषण वाले तरीके अपनाएं

वकील ने कहा-भगवान को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे बीमार हो रहे तो वो भी हैरान होंगे

एजेन्सी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में पटाखों पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन जरूरी है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने लोगों से कम प्रदूषण वाले तरीकों से त्योहार मनाने की अपील की।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा, अगर भगवानों को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो वे भी हैरान रह जाएंगे। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में लोगों



को जागरूक करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आदेश देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे व्यावहारिक और लागू करने योग्य बनाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक आधार पर सवाल उठाया। CJIने कहा कि लोगों को समझदार बनाना होगा और जागरूक करना होगा। उन्हें बताना होगा कि कौन से पटाखे ज्यादा नुकसानदायक हैं। हमें लोगों को अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उस समय केवल फुलझड़ियां जलती थीं और दीपक जलाए जाते थे।

वरिष्ट वकील पराजिता सिंह ने कहा कि सही तरीके से लागू किए बिना प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे। पिछले साल दिवाली से पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार हो गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यह छूट परंपराओं और पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की शर्तों के साथ दी गई थी।बेंच ने पराली जलाने से रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। केंद्र ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं पर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने पर सहमति दी।

माकपा सांसद का पुलिस-सीआरपीएफ पर आरोप

नियम नहीं तोड़ा, फिर भी मुझ पर टूट पड़े पुलिसकर्मी

एजेन्सी, नई दिल्ली

दिल्ली में 11 अक्तूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट का मामला सामने आया है। माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए।

उनका कहना है कि वह पुलिस की ओर से तय प्रतिबंधों का पालन करते हुए मीडिया से बात कर रहे थे, फिर भी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की ब्रिटास को रविवार को कनॉट प्लेस इलाके में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें एक्स-रे और चिकित्सकीय जांच के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।



ब्रिटास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह बैरिकेडिंग से काफी दूर थे और उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत भी नहीं की थी। उनके मुताबिक, वह अकेले थे और निषेधाज्ञा के तहत तय संख्या की सीमा के भीतर थे। इसके बावजूद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें क्यों पकड़ा, यह उनकी समझ से बाहर है। सांसद ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें करीब 50 मीटर तक घसीटा, पुलिस वाहन के अंदर उनके साथ मारपीट की और बाद में सड़क किनारे छोड़ दिया।

हाईकोर्ट से पेप्सिको को नहीं मिली राहत

एनर्जी ड्रिंक' लेबल के साथ नए उत्पादन पर रोक बरकरार

एजेन्सी, नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पेप्सिको को एनर्जी ड्रिंक लेबल के साथ अपने पेय पदार्थों का उत्पादन जारी रखने की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश में तत्काल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। हालांकि, अदालत ने एकल न्यायाधीश से इस फैसले के पीछे के स्पष्ट कारण एक सप्ताह के भीतर दर्ज करने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ पेप्सिको की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छह अक्टूबर के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने आदेश में विशिष्ट कारणों का जिक्र नहीं होने पर ध्यान दिया और कहा कि इन कारणों को दर्ज किया जाना जरूरी है, ताकि अपील पर विचार किया जा सके। पेप्सिको की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण



(एफएसएसएआई) ने कंपनी को अपने पेय पदार्थों से एनर्जी ड्रिंकशब्द हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद एकल न्यायाधीश ने कंपनी को इस मामले में सख्त कार्रवाई से संरक्षण दिया और पहले से मौजूद स्टॉक बेचने की अनुमति भी दी। हालांकि, कंपनी को स्टिंग एनर्जीऔर एड्रेनालिन रश नाम वाले पेय पदार्थों का एनर्जी ड्रिंकलेबल के साथ नया उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी गई। कंपनी के वकील ने कहा कि एक अन्य मामले में इसी तरह की राहत दूसरे पेय पदार्थ को दी गई थी। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वह मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहती, खासकर इसलिए क्योंकि अंतरिम राहत की पुष्टि से जुड़ी पेप्सिको की याचिका अभी एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। अदालत ने कहा, इस मामले में फिलहाल अंतरिम राहत लागू है। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि एकल न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किए कि पेप्सिको को एनर्जी ड्रिंक लेबल के साथ उत्पादन जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि रेड बुल से जुड़े मामले में ऐसी अनुमति दी गई थी।

पीठ ने निर्देश दिया कि छह अक्टूबर के आदेश के पैराग्राफ 13 में दर्ज टिप्पणियों के संबंध में कारण स्पष्ट किए जाएं, ताकि खंडपीठ इस मुद्दे पर विचार कर सके। एकल न्यायाधीश को यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा गया है। एफएसएसएआई की ओर से पेश वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

छह अक्टूबर को एकल न्यायाधीश ने एफएसएसएआई के उस निर्देश के बाद पेप्सिको के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था, जिसमें कंपनी से अपने पेय पदार्थों पर एनर्जी ड्रिंकका उल्लेख हटाने को कहा गया था। अदालत ने कंपनी को पहले से तैयार और एनर्जी ड्रिंकलेबल वाले पेय पदार्थों का मौजूदा स्टॉक बेचने की अनुमति दी थी। हालांकि, यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी इस लेबल के साथ नए उत्पादों का निर्माण नहीं कर सकती।

पेप्सिको ने एफएसएसएआई के उन आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिनमें पेय पदार्थों से एनर्जी ड्रिंकलेबल हटाने का निर्देश दिया गया था। एफएसएसएआई ने देशभर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे उत्पाद जब्त करने के लिए भी कहा था।

अखिल भारतीय कृषक परिषद की 70वीं बैठक में समस्याओं और नीतिगत सुधारों पर मंथन

कृषि नीति को किसान हितैषी बनाने सरकार पर दबाव बनाएंगे किसान

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

देश में कृषि नीति को किसान हितैषी बनाने और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब नीति निर्धारकों को समझाने तथा सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। किसान ऐसा समय देखना चाहते हैं, जब गर्व से कह सकें कि उनका बेटा भी किसान है। यह बात भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने राजस्थान के जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय कृषक परिषद की 70वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में शामिल होकर लौटे भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर केके अग्रवाल, जबलपुर ने बताया कि 8 एवं 9 अक्टूबर को आयोजित बैठक में देशभर से आए कृषक प्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं, वर्तमान कृषि नीति और उसमें आवश्यक सुधारों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में केंद्र सरकार को सौंपने और उसके



प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए किसानों की समस्याओं एवं मांगों का एक प्रारूप तैयार किया गया। अजय वीर जाखड़ ने कहा कि वर्तमान कृषि नीति के कारण किसानों की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में देशभर के किसानों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज समाज में लोग गर्व से यह कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं, लेकिन वह समय आना चाहिए, जब किसान भी गर्व से कहे कि उसका बेटा किसान है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब किसानों को समझाने के बजाय नीति निर्धारकों को किसानों की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराने और कृषि नीति में सुधार के लिए उन पर दबाव बनाने की जरूरत है। अग्रवाल के अनुसार, आगामी 13 नवंबर को दिल्ली में सरकार के प्रतिनिधियों और नीति निर्धारकों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। बैठक में मध्य प्रदेश से पहुंचे कृषक प्रतिनिधियों ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। कृषि नीति में सुधार के प्रस्तावों का मसौदा तैयार कर परिषद के अध्यक्ष को सौंपा गया। इंजीनियर केके अग्रवाल, नरेंद्र सिंह यादव, रूपेंद्र पटेल, रमेश पटेल, अविनाश ठाकुर और जितेंद्र देसी ने किसानों की ओर से अपने सुझाव रखे तथा जिले के किसानों का मांग पत्र भी अध्यक्ष को सौंपा।बैठक के दौरान जबलपुर में भारत कृषक समाज की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50 वर्षीय यात्रा विवरण पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। बैठक में जबलपुर जिले से सुभाष चंद्रा, व्हीके पंड्या, रामगोपाल पटेल, बिहारी पटेल, राजेश पटेल, अशोक पटेल, छोटे पटेल, लक्ष्मी पटेल, महेंद्र पटेल और अवसर पटेल सहित अन्य कृषक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चेरीताल में खुला नाला बना जानलेवा, एक साल से जिम्मेदारों की नजरें फेरने का आरोप

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर के चेरीताल क्षेत्र में सड़क किनारे स्थित पक्के नाले का क्षतिग्रस्त स्लैब पिछले करीब एक साल से लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण यह नाला अब हादसों को न्योता दे रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाले में गिरने से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। इसके बावजूद संबंधित स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो नाले के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। ऐसे में सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और पैदल स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम जबलपुर के आयुक्त से एक सप्ताह के भीतर जांच और कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा है। चेरीताल क्षेत्र में सड़क किनारे बने इस पक्के नाले पर नगर निगम की ओर से एनएमटी का निर्माण कराया गया था। नाले के ऊपर लगाया गया स्लैब क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही संबंधित हिस्सा दुर्घटना की आशंका वाला बना हुआ है। खुले और टूटे स्लैब के कारण नाले की स्थिति स्पष्ट रूप से



दिखाई नहीं देने पर राहगीरों के इसमें गिरने का खतरा बना रहता है। खासकर रात के समय और कम रोशनी में यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक नाले की मरम्मत नहीं होती, तब तक यहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी।

एक साल से खतरा, फिर भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं

क्षतिग्रस्त नाले की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों के अनुसार, नाले का स्लैब टूटने के बाद से ही दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद मौके पर न तो मजबूत बैरिकेड लगाए गए और न ही कोई ऐसा संकेतक लगाया गया है, जिससे दूर से ही लोगों को खतरे का पता चल सके। सुरक्षा के इन बुनियादी इंतजामों के अभाव में राहगीरों को स्वयं सतर्क रहकर निकलना पड़ता है। क्षेत्र में पैदल आने-जाने वाले स्कूली बच्चों को लेकर भी अभिभावकों की चिंता बढ़ी हुई है। बच्चे अक्सर रास्ते से गुजरते समय आसपास की परिस्थितियों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना किसी वयस्क व्यक्ति से अपेक्षित होता है। ऐसे में खुले नाले के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना किसी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संबंधित विभाग को किसी और हादसे का इंतजार करने के बजाय तत्काल सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत कराने के लिए कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत करा दी जाती और नाले के आसपास सुरक्षा के उपाय कर दिए जाते, तो दुर्घटना की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता था। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नागरिकों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले का क्षतिग्रस्त हिस्सा केवल आवागमन के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इसके आसपास गंदगी और दुर्गंध की समस्या भी बनी हुई है। नाले से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

गढ़ा रामलीला में गूंजे मंगलगीत, चारों राजकुमारों का विवाह

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

श्री रामलीला समिति गढ़ा जबालीपुरम के सिद्ध मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के विवाहोत्सव की भव्य लीला का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम का माता सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से तथा शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। चारों राजकुमारों के विवाह प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। विवाहोत्सव के अंतर्गत आयोजित पांव पखराई कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह के अनुज लेखराज सिंह 'मुन्ना भैया', स्थायी सदस्य सीताराम दुबे, डॉ. अखिलेश गुमास्ता, पार्षद प्रिया संजय तिवारी, पूजा श्रीराम पटेल एवं मंडल अध्यक्ष प्रणय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर भगवान श्रीराम एवं माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रीमती पूजा सतीश कोष्टा ने शक्ति के अभिनयकर्ताओं को अंग वस्त्र प्रदान किए। विवाहोत्सव में कुंअर कलेवा



एवं प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई। भजिया, जलेबी, गुजिया, दूध, खीर, फल, मिठाई एवं नमकीन सहित विभिन्न पकवानों की व्यवस्था डॉ. नीना भूपेंद्र उपाध्याय, नरेंद्र तिवारी एवं अरुण चौबे द्वारा की गई। समिति के संचालक अशोक मनोध्याय, अध्यक्ष एवं निर्देशक राजेश मिश्रा, महामंत्री एडवोकेट अरुण दीक्षित, लोकराम कोरी, रमाशंकर कटारे, राजेंद्र प्यासी, शरद दुबे कुररिया, उमाशंकर मिश्रा, हरीश मनोध्याय, दिनेश मिश्रा, सहित समिति के पदाधिकारियों ने पांव पखराई कर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त किया।

बरेला के परतला गांव में दो सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी, सोने-चांदी के सहित लाखों का माल ले गए चोर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

बरेला थाना क्षेत्र के परतला गांव में चोरों ने दो सूने मकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोर दोनों घरों से सोने-चांदी के जेवर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी सहित अन्य कीमती सामान ले गए। घटनाओं का पता लगने के बाद पीड़ितों ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परतला निवासी 30 वर्षीय सुनील डुमार ने पुलिस को बताया कि वह एचपी गैस प्लांट में काम करता है। 9 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे वह अपनी पत्नी प्रभा को लेकर रामपुर बेन मोहल्ला स्थित ससुराल चला गया था। घर पर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के राहुल चौधरी ने फोन कर बताया कि उसके घर के पीछे कुछ बर्तन और जेवर रखने के खाली पर्स पड़े हैं।सूचना मिलने पर सुनील घर पहुंचा तो अंदर



सामान बिखरा हुआ था। उसके बड़े भाई संजय कुमार के कमरे में भी सामान अस्त-व्यस्त मिला। संजय के घर पहुंचने पर दोनों ने सामान की जांच की तो टीवी, होम थिएटर, सोने की पांचाली, चांदी की एक जोड़ी पायल, पीतल की दो परात, दो कसेड़ी और सात हजार रुपये नकद गायब मिले। इसके अलावा संजय के कमरे से चांदी की एक जोड़ी मेंहदी, एक बाजूबंद, पांच नग हाय, एक छोटी करधन, कांसे की पांच थाली और पीतल की एक कसेड़ी भी गायब थी। इसी गांव की रहने वाली 55 वर्षीय माया डुमार ने भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह कभी-कभी अपनी बहू नीता के साथ जबलपुर के इम्पायर क्षेत्र में रहती हैं। करीब एक सप्ताह पहले वह अपने परतला स्थित मकान में ताला लगाकर बहू के घर चली गई थीं। 10 अक्टूबर को उनके देवर के बेटे सुनील ने फोन कर घर का ताला टूटा होने की जानकारी दी।

माया जब अपने घर पहुंचीं तो अंदर सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर सोने की एक जोड़ी झुमकी, चांदी की एक जोड़ी पायल, करधन और कांसे की सात थालियां गायब मिलीं। अज्ञात चोर ताला तोड़कर घर में घुसे और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सुनील डुमार की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 603/26 तथा माया डुमार की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 604/26 दर्ज किया है। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस चोरों का पता लगाने और चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

बूढ़ी खेरमाई मंदिर के पास दुकानों को लेकर विवाद, आधी रात आमने-सामने आए दो पक्ष

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

बूढ़ी खेरमाई मंदिर से लगे नर्मदा मैदान में दुर्गा उत्सव के दौरान अस्थायी दुकानें लगाने को लेकर रविवार देर रात विवाद की स्थिति बन गई। रात करीब दो बजे दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और हनुमानताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर उन्हें समझाया और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल मैदान में दुकानें लगाने की अनुमति को लेकर अंतिम निर्णय नगर निगम प्रशासन द्वारा लिया जाना है।

जानकारी के अनुसार, दुर्गा उत्सव के दौरान नर्मदा मैदान में अस्थायी दुकानें लगाने को लेकर पहले से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी। रविवार देर रात विश्व हिंदू परिषद के जिला सह-संयोजक अमित जाट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद दुकानदारों से दुकानें नहीं लगाने के लिए कहा। इस पर कारोबारी मोहम्मद शमीम, स्थानीय नागरिक साई कोरी और अन्य लोगों ने विरोध जताया। देखते ही देखते



दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ने लगी। मामले की जानकारी प्रशासन और पुलिस तक पहुंची तो अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और विवाद को आगे बढ़ने से रोका। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मैदान में दुकानें लगाने की अनुमति से संबंधित निर्णय नगर निगम प्रशासन के स्तर पर लिया जाएगा। इसके बाद मौके पर स्थिति सामान्य हुई।

दुकानों को लेकर विवाद सामने आने से पहले हिंदू संगठनों की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में विशेष समुदाय के व्यापारियों को मैदान में दुकानें लगाने से रोकने की मांग की गई थी। इसके बाद से ही इस विषय को लेकर क्षेत्र में असहमति बनी हुई थी।

आजीविका मिशन और आरसेटी से मिला प्रशिक्षण, पढ़ाई के साथ हर महीने कमा रहीं 8 से 10 हजार रुपये

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

हुनर और मेहनत के दम पर ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के कुंडम विकासखंड की कामिनी कुशराम इसकी प्रेरक मिसाल हैं। उन्होंने पारंपरिक गोंडी पेंटिंग की कला को अपनी आय का जरिया बनाकर न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि पढ़ाई के साथ अपने जरूरी खर्च भी स्वयं उठाने लगी हैं। कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबलपुर में कंप्यूटर साइंस की अंतिम वर्ष की छात्रा कामिनी पेंटिंग के माध्यम से हर महीने करीब 8 से 10 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। कामिनी की यह सफलता बताती है कि सही प्रशिक्षण, लगन और अपनी कला को रोजगार से जोड़ने की सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और आजीविका मिशन के माध्यम से मिले प्रशिक्षण ने उन्हें अपनी रुचि और हुनर को



पहचानने का अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने गोंडी पेंटिंग को केवल शौक तक सीमित रखने के बजाय इसे आय का साधन बनाने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण से मिली हुनर को निखारने की राह कामिनी ने वर्ष 2024 में आरसेटी और आजीविका मिशन के माध्यम से गोंडी पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वे पढ़ाई के साथ ऐसा काम करना चाहती थीं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

नवरात्र में दर्शन के लिए पहुंचा था परिवार

त्रिपुर सुंदरी मंदिर की पार्किंग से खाई में गिरी कार

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

नवरात्र के दौरान त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे एक परिवार के साथ हादसा हो गया। मंदिर परिसर की पार्किंग से एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और उनकी मदद की। जानकारी के अनुसार, नवरात्र के चलते त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। इसी दौरान पार्किंग क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते



खाई में जा गिरी। कार के खाई में गिरने से उसमें सवार दो लोगों को चोटें आईं। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। अचानक हुए इस हादसे से मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं के बीच भी चिंता देखी गई। हालांकि, हादसे के कारणों को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी जांच का विषय है कि कार पार्किंग में खड़ी थी या वहां से निकलते समय अनियंत्रित हुई। नवरात्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भी इन दिनों भक्तों की आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में मंदिर परिसर और पार्किंग क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। पार्किंग में पर्याप्त जगह, सुरक्षित मार्ग और खाई जैसे जोखिम वाले स्थानों पर उचित सुरक्षा इंतजाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश

धान पंजीयन में गड़बड़ी की आशंका, संदिग्ध किसानों के खेतों की होगी जांच

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने धान पंजीयन में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों के पंजीयन का निर्धारित मापदंडों के अनुसार सत्यापन करने और संदिग्ध मामलों की मौके पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में करीब सात हजार अधिक पंजीयन हुए हैं। इसे देखते हुए सिकमी पंजीयन, पहली बार पंजीयन कराने वाले किसानों, पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों और नए खसरों से जुड़े मामलों की विशेष जांच की जाएगी। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, राजस्व प्रकरणों, प्रसूति सहायता, एम्बुलेंस सेवाओं और निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर रविशंकर राय और अखिलेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सात हजार अधिक पंजीयन, संदिग्ध मामलों की होगी जांच कलेक्टर ने धान पंजीयन में खेतों की वास्तविक स्थिति और सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी का मिलान करने के निर्देश दिए। जहां दोनों में अंतर मिलता है, वहां अधिकारियों को मौके पर जाकर सत्यापन करना होगा। संयुक्त खातों और अन्य संदिग्ध



पंजीयन प्रकरणों की भी विशेष जांच की जाएगी, ताकि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही पंजीयन सुनिश्चित हो सके। लंबित शिकायतों पर प्राथमिकता सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने 50 और 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का विभागवार परीक्षण कर उनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बजट और दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं का नियमानुसार समाधान करने, लंबित शिकायतों के जवाब दर्ज करने और विभागीय रैंकिंग में सुधार लाने पर जोर दिया गया। सहायता और री-प्रोसेस के लिए लंबित आवेदनों का भी समय-सीमा में निराकरण करने को कहा गया। स्कूल शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, सामाजिक न्याय, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की रैंकिंग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रसूति सहायता का भुगतान प्रभावित होने पर संज्ञान विवाह के बाद महिलाओं की समग्र आईडी पति के परिवार में स्थानांतरित नहीं होने के कारण अमल-2.0 पोर्टल पर पति का विवरण प्रदर्शित नहीं होने और प्रसूति सहायता का भुगतान प्रभावित होने की समस्या भी बैठक में उठी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को स्वास्थ्य एवं श्रम विभाग, बीएमओ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी समग्र आईडी को यथासंभव पति

न्यूज ब्रीफ

माँ शारदेय नवरात्र में वृक्षारोपण कर प्रकृति माँ की आराधना



ग्वालियर। ग्वालियर में पहली बार माँ शारदेय नवरात्रि के दौरान प्रकृति माँ की आराधना का अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अपना योगदान देते हुए भ मोतीझील इलाके में स्थित एक पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया। इस वृक्षारोपण में पीपल नीम बरगद आम सहजन अर्जुन गुड़हल जैसे देशी पौधों को रोपा गया। इस मौके पर नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ग्वालियर एसडीएम प्रदीप शर्मा के साथ वरिष्ठ पत्रकार मचल सिंह बैस भी उपस्थित रहे। अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने वृक्षारोपण करने के बाद कहा कि लगातार बढ़ते? प्रदूषण को रोकने के लिए यह सबको पेड़ों का महत्व समझना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। ग्वालियर एसडीएम प्रदीप शर्मा ने कई पौधे रोपकर कटते पहाड़ खत्म होती हरियाली को बचाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि प्रकृति माँ की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है ।

सड़क पर आवागमन में बाधक अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई



ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सड़कों पर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के क्षेत्र क्रमांक 14 अंतर्गत सड़क पर बाधा उत्पन्न कर रहे स्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सड़क के किनारे बनाए गए लगभग 50 घरों के रैंप हटाए गए, जो सड़क पर आवागमन को प्रभावित कर रहे थे। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क को बाधामुक्त बनाना तथा आम नागरिकों के आवागमन को सुगम करना है।
नगर निगम द्वारा संबंधित क्षेत्र में सड़क की उपयोगिता एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

गारंटी पीरियड वाली सड़कों के पेचवर्क कार्य का आयुक्त अभिषेक चौधरी ने किया औचक निरीक्षण



ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर की सड़कों को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सड़क मरम्मत एवं पेचवर्क कार्य निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को देर सायं नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने मुरार क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पर गारंटी पीरियड की अवधि वाली सड़कों पर चल रहे पेचवर्क कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त श्री चौधरी ने मौके पर चल रहे सड़क मरम्मत कार्य का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि गारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर आवश्यकतानुसार पेचवर्क कार्य प्रभावी ढंग से कराया जाए, ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आयुक्त श्री चौधरी ने सड़क मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

स्वच्छता को अपनी आदत बनाना होगा:

जीडीए अध्यक्ष भदौरिया जीआईआईटी कॉलेज में पढ़ाया स्वच्छता का पाठ



■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।

स्वच्छता किसी एक की नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है तथा अपनी गली मोहल्ला एवं शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को अपनी आदत बदलनी होगी, तभी बदलेगा ग्वालियर। यह बात जीडीए अध्यक्ष मधुसुदन भदौरिया ने नगर निगम ग्वालियर आयोजित देश का सबसे बड़ा स्वच्छता संवाद के दौरान आम नागरिकों से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। नगर निगम ग्वालियर द्वारा ग्वालियर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को जीआईआईटी कॉलेज भिण्ड रोड पर किया गया। इस अवसर पर मेला उपाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह गुर्जर, नगर निगम स्वच्छता कंसलटेंट श्री अमित सिंह, प्रोफेसर डॉ रीता शर्मा, सुश्री वणिका शर्मा, श्री संजय सिंह एवं पीएस कुषवाह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने यह संकल्प लिया कि हम सभी मिलकर ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे एवं अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगें। जीडीए अध्यक्ष श्री मधुसूदन भदौरिया ने स्वच्छता संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि अपने वार्ड एवं मोहल्ले, कॉलेज परिसर को साफ रखने के लिए मिलकर प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आव्हान पर लोग स्वच्छता को अपना रहे हैं, आज अपना देश स्वच्छ भारत की दिशा में निरंतर आगे बड रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता होती है वहीं समृद्धि होती है तथा हम सभी यह जानते हैं कि स्वच्छता से हमारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए बहुत ही खराब है और प्लास्टिक की चीजों में गर्म खाना एवं भोजन का इस्तेमाल करना कैंसर का कारक है।

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित



■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सोमवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर सोजान सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बाल संरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम की रोकथाम, बाल विवाह उन्मूलन, बाल देखरेख संस्थाओं के निरीक्षण तथा जरूरतमंद बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास पर चर्चा की गई। बैठक में भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों की पहचान कर उनका समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा आगामी मेले में बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभावी अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का नियमानुसार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
बाल विवाह की रोकथाम एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर देखभाल एवं पुनर्वास सुविधाएं विकसित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पॉक्सो प्रकरणों में बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सपोर्ट पर्सन की कमी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। इसके अतिरिक्त कॉलेज स्तर पर जागरूकता गतिविधियों एवं आरटीओ लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने पर भी चर्चा की गई।

नगर निगम ग्वालियर को मिला अत्याधुनिक डॉग कैचिंग सीएनजी वाहन, महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में पशु प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आवारा श्वानों के सुरक्षित रेस्क्यू कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा क्रय किए गए अत्याधुनिक डॉग कैचिंग सीएनजी वाहन को महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार एवं निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम द्वारा क्रय किया गया यह वाहन एनिमल वेलफेयर बोर्ड की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस वाहन के माध्यम से शहर में आवारा श्वानों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने एवं रेस्क्यू संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, पशु कल्याण संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए श्वानों के प्रबंधन की कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। नगर निगम का उद्देश्य शहर में नागरिकों की सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है। अत्याधुनिक डॉग कैचिंग सीएनजी वाहन की उपलब्धता से संबंधित अमले को कार्य करने में सुविधा मिलेगी तथा शहर में श्वान प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

बदलने लगा मौसम का मिजाज, अस्पतालों में मरीज बढ़े

बदलते मौसम के साथ आप सुबह और शाम फिजा में ठंडक घुलने लगी

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह शुरू होने के साथ ही अब मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है 7 बदलते मौसम के साथ आप सुबह और शाम फिजा में ठंडक घुलने लगी है वहीं आज न्यूनतम तापमान में कल की अपेक्षा 0.5 डिग्री की कमी आई है। शहर का न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। मौसम में इस समय बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, दिन में तापमान सामान्य से कम हो गया है, जबकि रात का तापमान सामान्य से अभी भी 1.6 डिग्री अधिक चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही तापमान सामान्य के करीब हो जाएगा, मौसम विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आना प्रारंभहो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलेगा और सर्दी दस्तक दे सकती है बदलते मौसम का असर आप लोगों की सेहत पर भी पढ़ने लगा है जिसके चलते अब सर्दी जुकाम के अलावा वायरस और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है डॉक्टरों की राय है कि बदलते मौसम के साथ सेहत का विशेष ध्यान रखें ।

शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने मुख्य मार्गों से हटाया अस्थाई अतिक्रमण

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अवैध अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़कों से अवैध दुकानों, हाथ-ठेलों और अस्थाई अतिक्रमणों को हटवाया गया। मदाखलत के नोडल अधिकारी केषव सिंह चौहान ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देषानुसार मदाखलत अमले ने ग्वालियर विधानसभा अंतर्गत हजीरा चौराहा, किलागेट रोड, चार शहर का नाका, इंटक मैदान रोड सहित विभिन्न स्थानों पर खड़े यातायात में बाधक हाथ ठेले, फुटपाथी दुकानों एवं अन्य अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही की गई एवं आवागमन मार्ग क्लीयर कराया गया। पूर्व विधानसभा अंतर्गत ग्वालियर व्यापार मेले के अर्न्तगत मेले में दुकानो पर कुछ लोगो द्वारा सामान रखकर कब्जा कर लिया गया था जो कि कब्जाधारियो को दो दिवस में सामान सहित दुकान खाली करने की हिदायद दी गई तथा सामान नहीं हटाने पर सामान जब्ती की कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। दक्षिण विधानसभा अंतर्गत महाराज बाडा, सुभाष मार्केट नजरबाग मार्केट, टोपी बाजार, हेमू चौक, छापाखाना गॉधी मार्केट, माधौगंज मुख्य मार्ग से हाथ ठेले फुटफातियों के फड़ को हटवाकर मुख्य मार्ग क्लीयर कराया गया।

डिवाइडरों एवं सड़क किनारे अभियान चलाकर कराई सफाई, प्राथमिकता के साथ किया जा रहा कार्य

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण और हरित क्षेत्र को व्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से पार्क विभाग के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में डिवाइडरों, सड़क किनारे स्थित हरित पट्टियों एवं फुटपाथ क्षेत्रों की साफ-सफाई, पेड़-पौधों की छंटाई तथा अनावश्यक रूप से उगी गाजरघास को हटाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा अभियान के दौरान शहर के प्रमुख डिवाइडरों और सड़क किनारे के हरित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्वच्छ, सुंदर और हराभरा ग्वालियर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाया जा सके। यह अभियान अपर आयुक्त श्री प्रदीप सिंह तोमर, उपायुक्त श्री मुकेश बंसल एवं पार्क अधीक्षक श्री भूपेंद्र सासोड़े के निर्देशन में उद्यान निरीक्षक एवं समस्त उद्यान पर्यवेक्षकों द्वारा गठित दलों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उद्यान निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह राजावत द्वारा शिन्दे की छावनी से रामदास घाटी तक रोड डिवाइडर एवं रोड किनारे साफ सफाई कराई गई। इसके साथ ही उद्यान पर्यवेक्षक श्री दिनेश कुशवाहा द्वारा सूर्य नमस्कार से मृगनयनी गार्डन तक रोड डिवाइडर एवं रोड किनारे गाजर घास एवं सफाई कराई गई। उद्यान पर्यवेक्षक श्री सुभाष शाक्य द्वारा चंद्रबदनी नाका रोड डिवाइडर की सफाई कराई गई। उद्यान पर्यवेक्षक श्री राजकुमार नागर द्वारा डॉ हरी वाली पार्क में सूपा चलवाया गया एवं कटिंग करवाई एवं मेट्रो टावर के पीछे शिव शक्ति नगर कॉलोनी में सूपा चलवाया तथा झाडियों को काटा गया।

पूरा पंडाल जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा

रामलीला में पुष्पवाटिका, धनुषयज्ञ एवं शिव धनुष भंग की लीलाओं का मंचन हुआ

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

नव दुर्गा रामलीला सेवा समिति सेक्टर-सी दीनदयाल नगर के अध्यक्ष रणविजय सिंह कुशवाह द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया कि नवदुर्गा रामलीला सेवा समिति सेक्टर-सी दीनदयाल नगर में चल रहे रामलीला मंचन के दूसरे दिन भगवान श्रीराम की पुष्पवाटिका, धनुषयज्ञ एवं शिव धनुष भंग की लीलाओं का भव्य मंचन हुआ। कथा के क्रम में दर्शकों ने देखा कि गुरुदेव की पूजा हेतु पुष्प लेने राम पुष्पवाटिका पहुँचे, जहां उनकी भेंट माता सीता से हुई और दोनों एक-दूसरे में खो गए। तत्पश्चात जनकपुर में धनुषयज्ञ का आयोजन हुआ। अनेक देशों से आए राजा-महाराजाओं ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा जनक की व्यथा सुनकर मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से श्रीराम ने शिव धनुष भंग किया। इसी के साथ माता सीता ने श्रीराम को वरमाला पहनाई और पूरा पंडाल जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। मंच पर देवी-देवताओं की पुष्पवृष्टि का दृश्य दर्शकों के लिए अलौकिक अनुभव रहा।



धनुष भंग का समाचार सुनकर भगवान परशुराम सभा में पहुंचे। परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए जोशीले संवाद ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अंततः भगवान श्रीराम की विनम्र वाणी से परशुराम का क्रोध शांत हुआ और कथा का समापन भक्तिभाव से हुआ। रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भजन-कीर्तन और चौपाइयों की गूंज ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर शीतल सिंह भदौरिया, श्रीमति उमा भदौरिया, आदित्य भदौरिया (संचालक ग्रीन वुड स्कूल), सुरेश शर्मा (मेनेजर मंघा राम),पंकज राठौर समिति अध्यक्ष रणविजय सिंह कुशवाह, डी.पी.चौहान, रामगोपाल चौधरी,भारत परिहार,बनबारी श्रीवास्तव,सत्य प्रकाश यादव,डा.रविंद्र कुशवाह, राघवेंद्र कुशवाह,ब्रजपाल यादव,राजपाल तोमर, भारत तोमर, महावीर बघेल सहित समिति के पदाधिकारी एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।आज शाम 3 बजे भगवान श्रीराम की भव्य बारात विभिन्न झांकियों एवं बैंड-बाजों के साथ रामलीला मैदान, सेक्टर-सी दीनदयाल नगर से निकाली जाएगी।

संपादकीय

कॉकरोचों के डर से किलेबंदी

देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दृश्य हमने युद्धों के दौरान भी नहीं देखे। 1984 के सिख-विरोधी दंगे बेहद भयावह और जानलेवा थे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी तालाबंदी थी, लेकिन नागरिक अधिकार तब भी जिंदा थे। 10 अक्तूबर, 2026 को इतिहास में एक काली, डरावनी, दमनकारी तारीख के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने सडकों पर कीलें गाड़ दी थीं, ताकि कोई गाड़ी उन रास्तों से गुजरे, तो टायर में पंक्चर हो जाए। यह कैसा लोकतंत्र है? 7000 से अधिक युवाओं और कुछ नेताओं-सांसदों को हिरासत में लिया गया। रात होने लगी, तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। राजधानी दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई, सीमाएं लगभग सील कर दी गईं, ड्रोन उड़ते देखे गए मानो किसी बाहरी आक्रमण या आतंकी हमले की आशंका हो! मानो कोई विदेशी आक्रांता हमारे देश को लूटने आ रहा हो! मेट्रो ट्रेन के 45 स्टेशन बंद किए गए। न प्रवेश, न ही निकास और न ही इंटरचेंज! करीब 62 लाख लोग हररोज मेट्रो के जरिए इधर से उधर जाते हैं। कल्पना करें, कितने लोगों के पांव बांध दिए गए होंगे! करीब 250 ट्रेन रद्द कर दी गईं, जो दिल्ली से अन्य राज्यों को जाती थीं और वहां से दिल्ली की ओर आती थीं। लाखों भारतीय बंधक बनकर रह गए होंगे! बताया जाता है कि करीब 2 लाख रेल-यात्री प्रभावित हुए हैं। करीब 38,000 जवान, अर्द्धसैन्य बल और अन्य बलों के जवान दिल्ली में चारों तरफ तैनात कर दिए गए। नतीजतन जंतर-मंतर तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन कनॉट प्लेस की गलियों में युवा नारेबाजी करते रहे। पुलिस से कई जगह टकराव भी हुए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वे भी देश की ताकत हैं। अहम सवाल है कि क्या कॉकरोचों से इतने खतरे या उपद्रवों की आशंकाएं थी? क्या खुफिया एजेंसियों ने भी ऐसी रपटें दी थीं कि कॉकरोच राजधानी में उत्पात मचा सकते हैं और काट कर जहर फैला सकते हैं? सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायिक पीठ ने कहा था कि मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं।

मेट्रो, ट्रेनें, सडकें, परिवहन आदि के कारण आम नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार धरने-प्रदर्शन की वैकल्पिक जगह तय कर सकती है। चूंकि सरकार और पुलिस ने सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियों को हल्के में लिया, लिहाजा अब अदालत की अवमानना के तहत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को अदालत में तलब किया गया है। अदालत कठोर कार्रवाई करे, ताकि एक व्यापक संदेश जा सके। बहरहाल त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान औसतन 3-4 लाख लोग हररोज दिल्ली के बाजारों में आते हैं। करीब 5 लाख व्यापारी काम करते हैं। मेट्रो और ट्रेनें बंद कर दी गईं, तो खरीददार दिल्ली तक कैसे आएंगे? पेट्रोल पंपों तक पर भीड़ बहुत कम देखी गई। होटल, रेस्तरां, सिनेमा की बुकिंग रद्द कर दी गईं। व्यापार संगठनों का अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हुआ है! यह कैसी जन-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा है कि नागरिक ही पिस रहा है? यह धारणा मोदी सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। अंततः हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। क्या प्रदर्शनकारी कॉकरोच इतने खतरनाक और ताकतवर आंके गए हैं कि राजधानी दिल्ली को बंद, लगभग ठप, करने की नौबत आ गई? कॉकरोच जनता पार्टी कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, कुंठित और महत्त्वाकांक्षी युवाओं का समूह भर है, लेकिन युवाओं, खासकर जेन-जी, को एक ऐसा मंच मिल चुका है, जहां से वे अपना आक्रोश, गुस्सा और अपने मुद्दों को बयां कर सकते हैं। अब इन कॉकरोचों को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल की आप और वामपंथी दलों का सहयोग और समर्थन भी मिल गया है। कल तक जो चेहरे अज्ञात और अनजान थे, दिल्ली की इस किलेबंदी ने उन्हें युवा नेता बना दिया है। वे भविष्य में देश की जनता की धारणा के वाहक नेता भी बन सकते हैं। दिल्ली में ऐसी किलेबंदी, जवानों की फौज कमोबेश तब भी नहीं देखी गई, जब टिकैत के आह्वान पर 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली में धमक गए थे। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। टिकैत ने बोट क्लब पर रैली की थी।

भारत के आसमान पर किसका अधिकार?

कैलाश चन्द्र

> **मीडिया रिपोर्टों में जियो की परीक्षण उड़ान के लिए सितंबर 2027 का लक्ष्य तथा 2028 के आसपास शुरूआती कवरेज के लिए लगभग 90 से 100 उपग्रहों की योजना का उल्लेख किया गया है। आगे 2030 तक 400 से 450 और 2035 तक लगभग 1,600 उपग्रहों की तैनाती का लक्ष्य बताया गया है। फिर भी अंतरिक्ष परियोजनाओं में उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण की उपलब्धता, कक्षीय तैनाती, ग्राउंड स्टेशन, नियामक स्वीकृतियां और नेटवर्क परीक्षण एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।**

दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब बाजार, उत्पाद और ग्राहकों तक सीमित नहीं रह गई है। आज संचार नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और डिजिटल आधारभूत संरचना पर नियंत्रण किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति, सामरिक सुरक्षा और नीतिगत स्वायत्तता को प्रभावित करता है। ऐसे समय में भारत के प्रस्तावित लो-अर्थ-ऑर्बिट (एलईओ) सैटेलाइट नेटवर्क और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बीच उभरती प्रतिस्पर्धा को इंटरनेट सेवा की लड़ाई भर समझना अधूरा होगा। इसके केंद्र में बाजार के साथ तकनीकी क्षमता, नियामक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता के प्रश्न भी हैं। वैश्विक बाजारवादी शक्तियों का सीधे हस्तक्षेप है।

देखा जाए तो अक्टूबर 2026 में भारत में स्टारलिंक की मंजूरी और प्रतिस्पर्धा को लेकर मस्क की तीखी सार्वजनिक टिप्पणियों ने इस बहस को नया आयाम दिया है। दूसरी ओर, रिलायंस जियो की प्रस्तावित सैटेलाइट योजना से जुड़े आंकड़े भारतीय अंतरिक्ष एवं दूरसंचार क्षेत्र की संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पुष्ट तथ्यों, प्रस्तावित योजनाओं और उनके आधार पर निकाले जा रहे निष्कर्षों के बीच स्पष्ट अंतर रखना आवश्यक है। साथ ही, वैश्विक शक्तियों के दबाव और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रश्नों का अध्ययन भी जरूरी है। अब तक भारत में इंटरनेट का विस्तार मुख्यतः मोबाइल टावरों, ऑप्टिकल फाइबर और स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से हुआ है। इन माध्यमों ने शहरों से लेकर गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिर भी देश के अनेक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों, सीमावर्ती चौकियों और विरल आबादी वाले इलाकों में विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराना कठिन और महंगा हो सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट इस चुनौती का एक विकल्प है। इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से डेटा का संचार किया जाता है। एलईओ उपग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट होते हैं, इसलिए पारंपरिक भूस्थिर उपग्रहों की तुलना में कम विलंबता वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं।

यही कारण है कि एलन मस्क की स्टारलिंक, अमेजन की अमेजन लियो और अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। भारत में जियो और भारती समूह से जुड़ी वनवेब की योजनाएं इस प्रतिस्पर्धा को एक अलग राष्ट्रीय एवं औद्योगिक संदर्भ प्रदान करती हैं। अब यहां प्रश्न इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। नेटवर्क का स्वामित्व किसके पास होगा, उसका संचालन किसके नियंत्रण में रहेगा, डेटा और संचार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी तथा संकट के समय उस पर किसका प्रभावी नियंत्रण होगा, ये सभी विषय भारत की डिजिटल संप्रभुता से सीधे जुड़े हैं।

जियो की योजना : 1,600 उपग्रहों से जुड़ी महत्वाकांक्षा

मध्य-2026 की रिपोर्टों में रिलायंस जियो की लगभग 1,600 से 1,650 लो-अर्थ-ऑर्बिट उपग्रहों वाली प्रस्तावित योजना का उल्लेख किया गया है। इसके साथ भारत में लगभग 20 से 23 ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना की भी चर्चा हुई है। इस तरह के नेटवर्क का उपयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है। दूरदराज के गांवों और द्वीपों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार संपर्क मजबूत करना, मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहॉल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना तथा आपदा के समय स्थलीय नेटवर्क बाधित होने पर वैकल्पिक संचार देना इसके प्रमुख संभावित उपयोग हैं। उपयुक्त तकनीकी और नियामक व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल सैटेलाइट सेवाओं तथा डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी की संभावनाएं भी विकसित की जा सकती हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि यदि भारत में घरेलू कंपनी अपनी प्रस्तावित अंतरिक्ष-आधारित संचार क्षमता को सफलतापूर्वक विकसित कर पाती है, तो इससे देश के दूरसंचार और अंतरिक्ष उद्योग को नई संभावनाएं मिल सकती हैं।

मीडिया रिपोर्टों में जियो की परीक्षण उड़ान के लिए सितंबर 2027 का लक्ष्य तथा 2028 के आसपास शुरूआती कवरेज के लिए लगभग 90 से 100 उपग्रहों की योजना का उल्लेख किया गया है। आगे 2030 तक 400 से 450 और 2035 तक लगभग 1,600 उपग्रहों की तैनाती का लक्ष्य बताया गया है। फिर भी अंतरिक्ष परियोजनाओं में उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण की उपलब्धता, कक्षीय तैनाती, ग्राउंड स्टेशन, नियामक स्वीकृतियां और नेटवर्क परीक्षण एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें किसी भी स्तर पर देरी होने से पूरे कार्यक्रम की समयरेखा प्रभावित हो सकती है।

इसके बावजूद, दीर्घकालीन योजना का महत्व कम नहीं होता। यदि भारत में निजी क्षेत्र अंतरिक्ष-आधारित संचार नेटवर्क विकसित करने में सफल होता है, तो देश की तकनीकी क्षमता, औद्योगिक आपूर्ति-शृंखला और भविष्य की संचार जरूरतों के लिए विकल्प बढ़ सकते हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां प्रतिस्पर्धा का वास्तविक परिणाम किसी एक कंपनी की जीत या हार से नहीं, बल्कि भारत में निर्मित तकनीकी क्षमता और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ से मापा जाना चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पक्ष रक्षा और सामरिक संचार से जुड़ा है। जियो के कुछ प्रस्तावित उपग्रहों पर रक्षा संबंधी पेलोड लगाने की संभावना पर सरकारी स्तर पर चर्चा का उल्लेख किया गया है। यदि ऐसी व्यवस्था विकसित होती है और उसे आवश्यक स्वीकृतियां मिलती हैं, तो इससे सुरक्षित संचार, सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क और कुछ सामरिक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

इस विषय का एक पक्ष यह भी है कि किसी भारतीय कंपनी का उपग्रह नेटवर्क अपने आप भारतीय सशस्त्र बलों का स्वीकृत सैन्य संचार नेटवर्क नहीं बन जाता। इसके लिए सुरक्षा परीक्षण, तकनीकी एकीकरण, परिचालन प्रोटोकॉल और संबंधित सरकारी अनुमतियां आवश्यक होंगी। फिर भी, यह विषय एक बुनियादी प्रश्न उठाता है, क्या भारत को अपनी सामरिक संचार आवश्यकताओं के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए?

अब टेक्सटाइल का हब बनता भारत

डा. जयंती लाल भंडारी

वस्त्र निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बड़ी राहत और संबल प्रदान करते हुए सरकार ने आरओएससीटीएल योजना को 31 दिसंबर 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिससे आगामी वैश्विक त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने में भारी मदद मिल रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार मुख्य कपड़ा उद्योग (यार्न और फैब्रिक) ने अगस्त 2026 के दौरान 13.1 प्रतिशत की मजबूत मासिक वृद्धि और चालू वित्त वर्ष में 11.9 प्रतिशत की शानदार संचयी वृद्धि दर्ज की है। निश्चित रूप से गार्टेक्स और भारत टेक्स 2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से देश में डेनिम लेजर फिनिशिंग और तकनीकी वस्त्रों (टेक्निकल टेक्सटाइल्स) के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑटोमेशन आधारित स्मार्ट विनिर्माण को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है।



देश के प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्रों में आज भी कुशल कारीगरों और तकनीशियनों की पर्याप्त कमी महसूस की जा रही है। साथ ही, कपास का एक प्रमुख उत्पादक देश होने के बावजूद भारत की प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता वैश्विक औसत से काफी नीचे है। इन दिनों टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह रेखांकित किया जा रहा है कि भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और सरकार के द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र को दिए जा रहे बहुआयामी प्रोत्साहनों के दम पर टेक्सटाइल का नया ग्लोबल हब बनने की राह पर अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष जुलाई माह में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 ने न केवल वैश्विक टेक्सटाइल जगत में भारत के लिए एक स्वर्णिम इतिहास रचा है, बल्कि संपूर्ण विश्व को यह स्पष्ट और सशक्त संदेश भी दे दिया है कि भारत अब वैश्विक वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला का एक विश्वसनीय, अनिवार्य और प्रमुख ग्लोबल हब बनने की दिशा में अग्रसर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी 5-एफ दृष्टिकोण- फार्म (खेत), फाइबर (रेशा), फैक्टरी (कारखाना), फैशन और फॉरेन (विदेश) झ को पूरी तरह जीवंत करने वाला यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत टेक्सटाइल मेला बनकर उभरा है। निःसंदेह, इस वर्ष 2026 में देश का टेक्सटाइल सेक्टर लगभग 190 अरब अमरीकी डॉलर के बड़े आकार तक पहुंच चुका है, जिसका मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य विजन-2030 के तहत इसे बढ़ाकर 350 अरब डॉलर तक ले जाना है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार की नई टेक्सटाइल रणनीति और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संपन्न हो रहे मुक्त व्यापार समझौते अत्यंत प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेहद सुनियोजित रणनीति के तहत इन एफटीए समझौतों में टेक्सटाइल सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों के लिए दुनिया के सबसे बड़े, संपन्न और विकसित बाजारों में शून्य आयात शुल्क प्रवेश (जीरो-ड्यूटी एक्सेस) का सुगम मार्ग निश्चित ही प्रशस्त हुआ है।

इस दिशा में सबसे ऐतिहासिक कदम भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीटा) है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन सरकार ने भारतीय टेक्सटाइल और परिधानों पर पूर्व में लगने वाले 12 प्रतिशत तक के उच्च आयात शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस बड़ी और महत्वपूर्ण रियायत के बाद ब्रिटिश बाजार में भारतीय कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स हमारे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी देशों, जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में अत्यधिक सस्ते, आकर्षक और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इस समझौते के लागू होने तथा भारतीय निर्यातकों की उन्नत पूर्व-तैयारी के चलते वर्तमान में ब्रिटेन के बाजारों से भारतीय टेक्सटाइल की मांग में तीव्र और ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गत एक जून से भारत और ओमान के बीच लागू व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के अंतर्गत ओमान ने भी भारत के टेक्सटाइल उत्पादों सहित 99 प्रतिशत से अधिक घरेलू उत्पादों पर आयात शुल्क को पूरी तरह से शून्य कर दिया है।

संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहे व्यापारिक समझौतों ने पहले ही भारतीय टेक्सटाइल निर्यात को एक नई ऊंचाई और सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान भारत का कुल कपड़ा निर्यात 14.9 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में सालाना आधार पर 10.3 प्रतिशत की ठोस वृद्धि को दशार्ता है। इस समयावधि के दौरान कॉटन टेक्सटाइल के क्षेत्र में 18.0 प्रतिशत, मानव निर्मित वस्त्रों के क्षेत्र में 13.6 प्रतिशत और हस्तशिल्प के क्षेत्र में 44 प्रतिशत की उल्लेखनीय संचयी वृद्धि दर्ज की गई है।

वस्त्र निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बड़ी राहत और संबल प्रदान करते हुए सरकार ने आरओएससीटीएल योजना को 31 दिसंबर 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिससे आगामी वैश्विक त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने में भारी मदद मिल रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार मुख्य कपड़ा उद्योग (यार्न और फैब्रिक) ने अगस्त 2026 के दौरान 13.1 प्रतिशत की मजबूत मासिक वृद्धि और चालू वित्त वर्ष में 11.9 प्रतिशत की शानदार संचयी वृद्धि दर्ज की है। निश्चित रूप से गार्टेक्स और भारत टेक्स 2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से देश में डेनिम लेजर फिनिशिंग और तकनीकी वस्त्रों (टेक्निकल टेक्सटाइल्स) के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑटोमेशन आधारित स्मार्ट विनिर्माण को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल हब बनाने के लिए केंद्र सरकार पीएम मित्र (मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान) योजना के अंतर्गत देश के 7 प्रमुख राज्यों में 7 विशाल और अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। देश के इन सभी 7 राज्यों (तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) में 100 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है तथा आवश्यक पर्यावरण मंजूरियां भी प्राप्त हो चुकी हैं।

इन सातों पार्कों के पूर्ण विकसित और कार्यात्मक हो जाने के बाद देश में लगभग 70000 करोड़ रुपए का कुल निवेश आकर्षित होगा और तकरीबन 21 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्तमान समय में भी यह संपूर्ण क्षेत्र देश के 5.3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही, कपड़ा मंत्रालय की सामर्थ 2.0 योजना के तहत देश के युवाओं को आधुनिक मशीनों पर कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए री-स्किलिंग और अपस्किलिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में निरंतर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और घरेलू विनिर्माण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को अक्टूबर 2026 तक के लिए पूर्ण रूप से माफ कर दिया है। वैश्विक स्तर पर प्रचलित चाइना प्लस वन रणनीति के कारण अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनियां आज भारत को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक विनिर्माण साझेदार के रूप में देख रही हैं। इन्हीं बहुआयामी और दूरदर्शी सुधारों के परिणामस्वरूप प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र के समग्र परिदृश्य को नकारात्मक से उन्नत करके स्थिर (स्टेबल) घोषित कर दिया है।

महामति श्री प्राणनाथ प्रगटन महोत्सव पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया सेवाभावियों का सम्मान कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

महामति श्री प्राणनाथ जी के प्रगटन महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राधा कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, भोपाल द्वारा भवानी चौक, पेबल-वे, बागमुगालिया, भोपाल में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विधिवत पूजन के साथ हुआ शिविर का शुभारंभ सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुरूप शिविर का शुभारंभ महामति श्री प्राणनाथ जी की विधिवत पूजा-अर्चना एवं पाठ के साथ हुआ। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, शिवाजी नगर, भोपाल के महंत परम पूज्य 108 श्री पं. रूपराज जी महाराज ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में श्रद्धा, सेवा और मानव कल्याण की भावना प्रमुख रूप से दिखाई दी। शिविर में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी ने निःस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सहयोगियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने मानव सेवा के इस कार्य की सराहना करते हुए समाज में सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया।





श्री प्राणनाथ शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री बी.आर. त्रिपाठी जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में महामति श्री प्राणनाथ जी के वचनों 'तुम सेवा से पाओगे पार। सुख शीतल करूँ संसार।' का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव सेवा के माध्यम से ही समाज में सुख, शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम के दौरान महामति श्री प्राणनाथ जी के संदेशों एवं साहित्य का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भोपाल के पुजारी पं. अमरनाथ शर्मा, श्री प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट, पन्ना धाम के न्यासी श्री उपदेश शर्मा, श्री राधा कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, भोपाल के अध्यक्ष श्री वी.जी. शर्मा, समाजसेवी श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव, जोशी जी, कॉलोनी के अध्यक्ष श्री गुप्ता, एडवोकेट श्री एच.के. शर्मा, श्री रामावतार प्रणामी, श्री एस. के. गुप्ता जी, श्री एस. एस. कुमार जी, श्री बाय. एन. द्विवेदी, श्री ओमबीर सिंह, श्री बी एम मालवीय, श्री विजय पाठक जी सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री राधा कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, भोपाल ने शिविर को भव्य एवं सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी संस्थानों, चिकित्सकों और सेवाभावियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। समिति ने विशेष रूप से दा काउंटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉ. सिंघई एवं उनकी पूरी टीम, सेवासदन नेत्र चिकित्सालय, भोपाल तथा बेस्ट फिजियो एंड रिहैब की टीम के योगदान की सराहना की। समिति ने उन सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस जनकल्याणकारी आयोजन में योगदान दिया। प्रार्थना की गई कि सभी सहयोगियों पर उनकी कृपा बनी रहे तथा वे सदैव स्वस्थ, सुखी और निरोग रहें।

रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, बीना एवं गुना होकर प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल होकर चलेंगी 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा भोपाल मंडल होकर विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे तथा नियमित ट्रेनों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। प्रमुख स्पेशल ट्रेनें इस प्रकार हैं: 1.रानी कमलापति-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (01667/01668): 12 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में दोनों दिशाओं में 11-11 फेरे। 2. रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक पूजा स्पेशल (02191/02192): अक्टूबर एवं नवंबर में निर्धारित तिथियों पर दोनों दिशाओं में 4-4 फेरे। 3.लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ स्पेशल (01123/01124): 11 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक निर्धारित अवधि में संचालन।4.पुणे-गोरखपुर दैनिक स्पेशल (01415/01416): अक्टूबर एवं नवंबर में दोनों दिशाओं में 32-32 फेरे। 5.लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर दैनिक स्पेशल (01079/01080): अक्टूबर एवं नवंबर में दोनों दिशाओं में 32-32 फेरे। 6.हडपसर-गाजीपुर सिटी स्पेशल (01431/01432): 13 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक दोनों दिशाओं में 12-12 फेरे। 7.लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस स्पेशल (01051/01052): 14 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में संचालन। 8.सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल एवं वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (04226/04225): अक्टूबर एवं नवंबर में दोनों दिशाओं में 4-4 फेरे। ये ट्रेनें बीना, रानी कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों पर ठहरेंगी।9.अजमेर-रांचीपूजा स्पेशल (09619 /09620): अक्टूबर से नवंबर 2026 तक दोनों दिशाओं में 9-9 फेरे, गुना स्टेशन पर ठहराव। 10.जोधपुर-चेन्नई बीच पूजा स्पेशल (04815/04816): अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में संचालन। यह ट्रेन गुना, बीना, भोपाल एवं इटारसी स्टेशनों पर ठहरेगी। 11.इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल (04170 /04169) : अक्टूबर से नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में संचालन। 12.उधना-प्रयागराज स्पेशल: अक्टूबर से नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में संचालन। ये ट्रेनें रूठियाई-गुना मार्ग से होकर चलेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन ट्रेनों से विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए यात्रा के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और नियमित ट्रेनों में यात्री भार कम करने में सहायता मिलेगी। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन की तिथि, समय-सारणी एवं ठहराव की जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, रेलवन ऐप अथवा रेलवे पूछताछ सेवा 139 से प्राप्त करें।

लोड शेडिंग के कारण की जा रही बिजली कटौती पर सौंपा ज्ञापन



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भोपाल के ग्रामीण इलाकों में लोड शेडिंग के चलते लगातार अघोषित बिजली कटौती जारी है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में तथा विभाग के जमीनी अमले द्वारा की जा रही लापरवाही के विरोध में प्रदेश कांग्रेस सचिव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विष्णु विश्वकर्मा ने ऊर्जा विभाग के सचिव तथा पॉवर मैनेजमेंट कंपनी मप्र के प्रबंध निदेशक विशेष गढ़पाले को ज्ञापन दिया। किसान नेता विष्णु विश्वकर्मा ने ज्ञापन में बिजली कटौती से उत्पन्न कई समस्याओं को उठाते हुए उनके निराकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में विराजित देवी के झांकी पंडालों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियो समेत अन्य धार्मिक आयोजन भी बिजली कटौती के कारण नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है, शाम से देर रात तक होने वाली कटौती के कारण आपराधिक घटनाओं की संभावना भी कांग्रेस सचिव द्वारा अपने ज्ञापन में जताई गई है। वहीं पॉवर मैनेजमेंट कंपनी मप्र के प्रबंध निदेशक विशेष गढ़पाले ने इस मामले पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अघोषित बिजली कटौती न हो इस बावत अधिकारियों को निर्देशित देने की बात कही।

टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत 10 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 10 करोड़ की छूट

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल/ग्वालियर**



मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सितंबर माह लाभदायक रहा। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स में बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसी क्रम में सितंबर 2026 में कंपनी के कार्यक्षेत्र के कुल 10 लाख 11 हजार 291 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों में कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक की उल्लेखनीय छूट का लाभ मिला। इनमें भोपाल रीजन के 8 लाख 17 हजार 227 उपभोक्ताओं को 7 करोड़ 33 लाख 47 हजार रुपये तथा ग्वालियर रीजन के 1 लाख 94 हजार 64 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 66 लाख 76 हजार रुपये की छूट प्रदान की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। स्मार्ट मीटर न केवल ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण रखने और आर्थिक बचत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) बिजली उपयोग करने पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा श्री कैलाश कुमार चौधरी, प्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) से संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को घरेलू स्मार्ट मीटर से मिलने वाले फायदे 1. ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। 2. बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।3. ऐप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। 4. ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा

भोपाल। मध्यप्रदेश में साइबर अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रतलाम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी के प्रकरण का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ठगी की राशि में से लगभग 20 लाख रुपये होल्ड कराने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में से दो आरोपियों को हैदराबाद तथा एक आरोपी को धारवाड़, कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। प्रकरण में फरियादी, जो कुवैत में मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में रतलाम में रह रहे थे, को 15 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया गया। पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े व्यक्ति से बातचीत जैसे गंभीर आरोप लगाकर फरियादी को भयभीत किया।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में करें संतुष्टिपूर्ण निराकरण

छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करें सभी अधिकारी : एडीएम सुमित पांडे

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



एडीएम सुमित पांडे ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मेस की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एडीएम श्री पांडे सोमवार को समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एडीएम श्री प्रकाश नायक, एडीएम श्री महेंद्र सिंह कवचे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसमस्याओं के निराकरण और लंबित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा की गई। पांडे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शहर के विकास और शासकीय परिसरों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए पुनर्घनत्वीकरण (रीडेंसिफिकेशन) कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। एडीएम श्री पांडे ने संबंधित विभागों को कार्ययोजना के संबंध में तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

57वीं जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर स्टडी सर्किल की बैठक संपन्न

रिफंड से लेकर आईटीसी तक, जीएसटी के बदलावों पर मंथन, करदाताओं को मिल सकती है राहत

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**





भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की ओर से जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों और कर व्यवस्था में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों पर विशेष स्टडी सर्किल का आयोजन किया गया। एसजीएसटी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सीए नवनीत गर्ग ने जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों, उनके व्यावहारिक प्रभावों तथा करदाताओं और कर सलाहकारों के लिए उनकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनेन्द्र वैद्य ने की। सीए नवनीत गर्ग ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने से जुड़े पांच प्रमुख सुधारों पर चर्चा की गई। इन सुधारों में रिफंड प्रक्रिया को तेज करना, गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में बदलाव, अभियोजन की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना, ईमानदार खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को संरक्षण देना तथा बायोमेट्रिक आधारित पंजीयन व्यवस्था शामिल हैं। इस अवसर पर सचिव प्रशांत काबरा, कोषाध्यक्ष जयंत जोशी, सह सचिव प्रेम मोटवानी, कार्यकारिणी सदस्य संतोष चौरे एवं संदीप साहू सहित बड़ी संख्या में कर सलाहकारों ने भाग लिया। सीए गर्ग ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से पात्र करदाताओं को राहत मिल सकती है और कारोबार में पूंजी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए समय पर रिफंड मिलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी कार्यशील पूंजी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अभियोजन की सीमा 5 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव के महत्व को भी समझाया और कहा कि ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य कर अनुपालन तथा दंडात्मक कार्रवाई के बीच उचित संतुलन स्थापित करना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनेन्द्र वैद्य ने ईमानदार खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुरक्षा को महत्वपूर्ण सुधार बताते हुए कहा कि जीएसटी व्यवस्था में वास्तविक कारोबार करने वाले करदाताओं के हितों का संरक्षण आवश्यक है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक पंजीयन व्यवस्था को फर्जी पंजीयन पर अंकुश लगाने और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संबंधित अधिसूचनाओं, नियमों और लागू होने की तिथियों के आधार पर समझना चाहिए।

रणजी ट्रॉफी : मुंबई के लिए ऐसा करने वाले छठे गेंदबाज

तुषार देशपांडे की हैट्रिक



सानिया और माया ने लागोस में ही जीते खिताब
विमेंस डबल्स में भी चैंपियन बनीं

मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

- जहांगीर खोतः 1943-44 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में बड़ौदा के खिलाफ।
- उमेश कुलकर्णीः 1963-64 में आनंद में गुजरात के खिलाफ।
- अब्दुल इस्माइलः 1973-74 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ।
- रॉयस्टन डायसः 2023-24 में पटना में बिहार के खिलाफ।
- शार्दुल ठाकुरः 2024-25 में मुंबई के बीकेसी मैदान पर मेघालय के खिलाफ।

देशपांडे की हैट्रिक ने मुंबई को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। चंडीगढ़ के सामने अब मुंबई की पहली पारी के स्कोर तक पहुंचने और मुकाबले में वापसी करने की कठिन चुनौती है।

एजेन्सी, मुंबई

तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी 2026-27 में चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले के दूसरे दिन शानदार हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वह रणजी ट्रॉफी में मुंबई की ओर से हैट्रिक लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में देशपांडे ने लगातार तीन गेंदों पर अर्जुन आजाद, शिवम भांबरी और दीपेंद्र कुश को आउट किया। उनकी इस उपलब्धि से चंडीगढ़ की टीम मुंबई के पहली पारी में बनाए गए 429 रन के जवाब में छह विकेट पर 37 रन बनाकर संकट में आ गई। देशपांडे ने खबर लिखे जाने तक 17 रन देकर पांच विकेट हासिल कर लिए थे।

मुंबई के लिए हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल

देशपांडे से पहले मुंबई की ओर से रणजी ट्रॉफी में पांच गेंदबाज हैट्रिक ले चुके हैं। इस सूची में जहांगीर खोत, उमेश कुलकर्णी, अब्दुल इस्माइल, रॉयस्टन डायस और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं।

देशपांडे की वजह से मुंबई की मैच पर पकड़ मजबूत

बात करें मुकाबले की तो मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 429 रन बनाए। कप्तान सिद्धेश लाड़, मुशीर खान, तनुष कोटियान और मोहित अवस्थी ने शानदार अर्धशतक ठोका था। लाड़ ने 86, मुशीर ने 65, अवस्थी ने 56 और कोटियान ने 58 रन जड़े। इसके अलावा, तुषार ने गेंद से पहले बल्ले से भी टीम को योगदान दिया था। तुषार ने 44 रनों की पारी खेली थी। वहीं, आयुष म्हात्र ने 48 रन बनाए थे। देशपांडे की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से मुंबई ने चंडीगढ़ पर 351 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। मुंबई ने चंडीगढ़ को फॉलो-ऑन दे दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक चंडीगढ़ ने बिना कोई रन बनाए एक विकेट गंवा दिया है।

देशपांडे के शानदार प्रदर्शन की वजह से मुंबई की पकड़ मजबूत हो गई है। मुंबई के गेंदबाज, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे में अगर कल ही वो चंडीगढ़ के खिलाफ जीत हासिल कर लें तो कोई हैरानी नहीं होगी।

भारत-श्रीलंका वनडे दिल्ली से अहमदाबाद स्थानांतरित होने की खबरें गलत : सैकिया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को उन खबरों को गलत बताया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाला पहला वनडे मुकाबला अहमदाबाद स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय बोर्ड ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।



यह स्पष्टीकरण दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे बड़े स्तर के ढांचागत सुधार कार्यों के बीच आया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ स्टेडियम में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था लगाने के साथ पिचों और आउटफील्ड को नए सिरे से तैयार कर रहा है। इसी कारण मुकाबले के आयोजन स्थल को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। सैकिया ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ह्लदिल्ली में निर्धारित भारत-श्रीलंका वनडे मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने संबंधी खबरें सही नहीं हैं। बीसीसीआई ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

उन्होंने कहा, ह्लहम मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए बीसीसीआई के आधिकारिक संचार का ही संदर्भ लें। साथ ही, यह दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 दिसंबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं, तीसरा वनडे 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निर्धारित है। ये मुकाबले भारत के लिए 2027 में होने वाले पुरुष वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से अहम हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम अपनी रणनीति और संयोजन को अंतिम रूप देना चाहेगी।

दिल्ली की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को नई जर्सी देगा स्केचर्स

एजेन्सी, नई दिल्ली

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सत्र के लिए स्केचर्स को आधिकारिक परिधान प्रायोजक और यूफ्लेक्स को आधिकारिक साझेदार घोषित किया है। इस करार के तहत स्केचर्स दिल्ली की पुरुष और महिला टीमों को विभिन्न आयु वर्गों में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए परिधान उपलब्ध कराएगा। ये टीमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू टूर्नामेंटों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हैं।

डीडीसीए के अनुसार पिछले सत्रों में पुरुष और महिला टीमों की मैच जर्सी तथा अभ्यास किट पर संघ को लगभग 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। स्केचर्स के प्रायोजन से इस सत्र में खिलाड़ियों को बेहतर परिधान उपलब्ध कराने के साथ संघ के इस खर्च की भरपाई करने में मदद मिलेगी।डीडीसीए ने बताया कि यूफ्लेक्स भी 2026-27 सत्र के लिए आधिकारिक साझेदार के रूप में जुड़ा है। समझौते की शर्तों के अनुसार, कंपनी का लोगो टीम की किट पर दिखाई देगा। इन दोनों साझेदारियों से संघ को अपने परिधान संबंधी खर्च की भरपाई के साथ अतिरिक्त प्रायोजन राजस्व मिलने की उम्मीद है।

यह पहल दिल्ली क्रिकेट के व्यावसायिक साझेदारों का दायरा बढ़ाने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा, ह्लहम 2026-27 सत्र के लिए स्केचर्स और यूफ्लेक्स का स्वागत करते हुए प्रसन्न हैं। दुनिया भर में पहचान रखने वाले ब्रांडों और उद्योग जगत के अग्रणी समूहों के साथ रणनीतिक साझेदारी करना दिल्ली में मजबूत और टिकाऊ क्रिकेट व्यवस्था विकसित करने की हमारी सोच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये साझेदारियां हमारी घरेलू क्रिकेट व्यवस्था के पेशेवर स्तर को बेहतर बनाने के साथ दिल्ली क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू को भी दशार्ती हैं। हमारी प्राथमिकता प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाना और पुरुष तथा महिला टीमों को उच्चस्तरीय संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है।

स्केचर्स के प्रवक्ता ने कहा कि डीडीसीए जैसे प्रमुख खेल संस्थान के साथ साझेदारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में दिल्ली का समृद्ध इतिहास रहा है और यह सहयोग कंपनी को देश की प्रमुख घरेलू क्रिकेट व्यवस्था से सीधे जुड़ने का अवसर देता है।

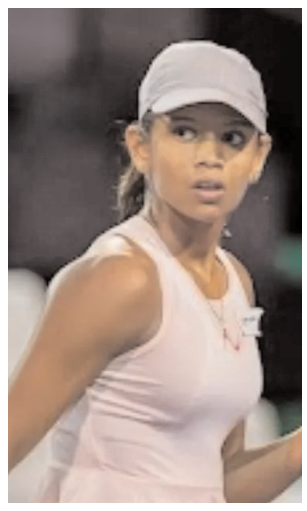
माया ने तोड़ा सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड

17 साल में महिला प्रो-टेनिस चैंपियन, सबसे युवा भारतीय बनीं

एजेन्सी, नई दिल्ली

17 साल की भारतीय टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन रेवती ने सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने रविवार को पुर्तगाल के लागोस में क्ळञ्ह्र35 टूर्नामेंट जीत लिया है। वे यह टाइटल जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी हैं।

17 साल 3 महीने की माया ने विमेंस सिंगल्स के फाइनल में स्पेन की सीलिया सरविनो को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। सानिया मिर्जा ने 2004 में 17 साल 10 महीने की उम्र में खिताब जीता था। दुनिया की 1038वें नंबर की खिलाड़ी माया ने मुख्य ड्रॉ के पहले राउंड में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर-246 जुस्तिना मिकुलस्काइट को 7-6(1), 6-1 से हराया। पहले सेट में वह 0-5 से पिछड़ गई थीं, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए सेट टाईब्रेकर में जीत लिया।



दूसरे राउंड में माया ने अर्जेंटीना की बर्टा बोनार्डी को 6-2, 6-0 से हराया। फाइनल में पहला सेट जीतने के बाद माया ने मन ही मन गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैच के बाद उन्होंने कहा, ह्यमुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा दबाव ले रही हूं। तनाव कम करने के लिए मैंने मन में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ह्यपहला खिताब हमेशा खास होता है। इस हफ्ते की कई अच्छी यादें मेरे साथ रहेंगी। इस जीत से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं बड़े स्तर पर मुकाबला कर सकती हूं। माया ने यूक्रेन की येलिजवेता कोट्लियार के साथ डबल्स खिताब भी अपने नाम किया। उन्होंने अपनी जोड़ी दार के साथ फाइनल में मिन लियू और कालोर्टा मोचिया को 0-6, 6-2, 10-7 से हराया। पहला सेट 0-6 से गंवाने के बाद माया और कोट्लियार ने दूसरे सेट में वापसी की। इसके बाद निर्णायक सुपर टाईब्रेकर 10-7 से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन

कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों सहित अन्य लंबित विषयों की विस्तृत समीक्षा

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी एल-1 अधिकारी अगले 4 दिनों में ही शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर सीएम हेल्पलाइन शिकायतें संतुष्टि से बंद कराने का प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समुचित परीक्षण के बाद ही शिकायतें कार्यक्षेत्र से बाहर की जाएं और किसी भी शिकायत को 10 से अधिक बार कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतें बंद करवाने में सभी विभागों का प्रदर्शन राज्य के औसत से अधिक तथा संतुष्टि से बंद शिकायतों का प्रतिशत 50 से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबल, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र और समग्र से जुड़ी शिकायतो में संबंधित विभाग आवश्यक समन्वय कर गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए समग्र होना अनिवार्य है इसलिए जिले के सभी निवासियों के समग्र बनाए जाने हैं। उन्होंने समग्र पंजीयन और सत्यापन में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह विभाग की 100+ दिवसों को शिकायतों की भी समीक्षा की तथा सभी थानों द्वारा लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक में ये निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में, विशेषकर सेवा सम्बन्धी विषयों में, समय रहते आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए जिससे अवमानना की स्थिति नहीं बने। समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि आगामी त्यौहारों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में रेंकिंग में शामिल मापदंड में प्रदर्शन में सुधार लाया जाए और किसी भी विषय में विभागों का प्रदर्शन बॉटम-10 में नहीं पाया जाए। कलेक्टर ने बताया कि समय सीमा पत्रकों पर कार्यवाही पूर्ण होने पर जानकारी अपडेट करने के लिए विभागीय कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अधिकारियों को अपडेशन के लिए निर्धारित दिवसों पर आपरेटर सहित उपस्थित होना रहेगा। उन्होंने बैठक में भूमि आवंटन, विजन डाक्यूमेंट, लंबित एचटी बिजली देयकों का भुगतान, विभागों के निष्क्रिय बैंक खाते, इत्यादि की भी समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, जनपद सीईओ, सीएमओ, सीएमएचओ, एसडीओपी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे जबकि अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे।

अर्बन कॉन्क्लेव में शहरी विकास, तकनीक और निवेश पर होगा मंथन



एक सत बुलेटिन, इंदौर

मध्यप्रदेश में शहरी विकास की नई संभावनाओं, आधुनिक तकनीक और निवेश को लेकर 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सोमवार को आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में आयोजन के सुचारू संचालन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। आयुक्त ने कहा कि कॉन्क्लेव में नगरीय विकास के नए आयामों, आधुनिक तकनीकी समाधानों और निवेश की संभावनाओं पर सार्थक एवं परिणामोन्मुखी विचार-विमर्श किया जाए, ताकि प्रदेश के शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए नए विकल्प तलाशे जा सकें। कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के नियोजित विकास, री-डेंसिफिकेशन नीतियों, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वैज्ञानिक भूमि उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। शहरी विकास के आधुनिक मॉडल और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा। आयुक्त भोंडवे ने विषय-विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, निवेशकों और नीतिगत संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कॉन्क्लेव का उद्देश्य नवाचारों, आधुनिक तकनीक और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शहरों के नियोजित एवं सतत विकास को नई दिशा देना है।

अंबाह उपजेल में दिव्यांगता परीक्षण एवं पहचान शिविर आयोजित 8 बंदियों का किया गया परीक्षण



एक सत बुलेटिन, मुरैना

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार तथा सामाजिक न्याय विभाग, मुरैना के उपसंचालक एवं डिप्टी कलेक्टर आर.के. सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं जिला दिव्यांग मेडिकल बोर्ड, मुरैना द्वारा अंबाह उपजेल में दिव्यांगता परीक्षण एवं पहचान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों में संभावित दिव्यांगता की पहचान कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय जांच एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना था। शिविर में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं जिला दिव्यांग मेडिकल बोर्ड की विशेषज्ञ टीम द्वारा बंदियों का आवश्यकतानुसार परीक्षण एवं प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया। इस दौरान शारीरिक, श्रवण, दृष्टि, मानसिक एवं बौद्धिक सहित विभिन्न प्रकार की संभावित दिव्यांगताओं की पहचान के लिए आवश्यक परीक्षण किए गए। शिविर में कुल 8 बंदियों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान सभी 8 बंदियों में दिव्यांगता के लक्षण अथवा संभावना पाए जाने पर उन्हें आगे की चिकित्सकीय जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया के लिए चिह्नित किया गया। साथ ही, उन्हें नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) तथा आवश्यक पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। शिविर में अंबाह उपजेल अधीक्षक श्री रफी हुसैन सहित चिकित्सकीय दल एवं पुनर्वास विशेषज्ञ उपस्थित रहे। शिविर के सफल आयोजन में जेल प्रशासन तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, मुरैना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगता की समय पर पहचान एवं समुचित मूल्यांकन से संबंधित व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार पुनर्वास सेवाएं, सहायक उपकरण, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा शासन की विभिन्न दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता मिलती है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न संस्थानों एवं क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि दिव्यांगता से संबंधित जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके।

ग्राम पंचायतों में रिक्त उपसरपंच पदों के निर्वाचन के लिए 15 अक्टूबर को सम्मिलन

मुरैना! मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त उपसरपंच पदों की पूर्ति के लिए गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सम्मिलन आयोजित किया जाएगा। पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के अंतर्गत पंच पदों के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2026 को की जा चुकी है। आयोग के निर्देशानुसार, जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व से उपसरपंच के पद रिक्त हैं, उन्हें भी निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उपसरपंच पदों के निर्वाचन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के निर्वाचित पंचों एवं सरपंच का सम्मिलन बुलाया जाएगा।उपसरपंच पदों के निर्वाचन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के निर्वाचित पंचों एवं सरपंच का सम्मिलन बुलाया जाएगा। निर्वाचन की समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 तथा संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), मुरैना द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक राजीव कुमार यादव 'मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' से सम्मानित

एक सत बुलेटिन, भोपाल।



पश्चिम मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री राजीव कुमार यादव को उनकी उत्कृष्ट, समर्पित एवं सराहनीय सेवाओं के लिए रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में आयोजित समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित 'मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' (RSM) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सुश्री सोनाली मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान श्री यादव के रेल सुरक्षा, यात्री संरक्षा, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। श्री राजीव कुमार यादव ने वर्ष 1998 में रेलवे सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं प्रारंभ कीं। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पदों पर कार्य करते हुए प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन और समर्पित कार्यशैली की विशिष्ट पहचान बनाई। उग्रवाद एवं नक्सल प्रभावित रेल क्षेत्रों में कार्य करते हुए उन्होंने स्थानीय पुलिस, सेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण रेलवे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेल परिचालन को सुचारु बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व एवं सेवाकाल में रेलवे संपत्ति की चोरी करने वाले गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, यात्रियों एवं महिलाओं की सुरक्षा, संकटग्रस्त एवं लावारिस बच्चों के बचाव तथा मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया गया। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन तथा यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त, श्री यादव ने रेलवे सुरक्षा बल के आधारभूत ढांचे के विकास, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार, आधुनिक सुरक्षा तकनीकों के उपयोग तथा बल के कर्मचारियों के कल्याण एवं कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने अपराध नियंत्रण, यात्रियों के सामान की चोरी की रोकथाम, साइबर सुरक्षा तथा रेल परिचालन को प्रभावित करने वाली असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण को प्राथमिकता दी। श्री यादव को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पूर्व में भी डीजी इंसिग्नियासिक्योरिटी शील्ड एवं महाप्रबंधक पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों एवं प्रशस्तियों से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राजीव कुमार यादव को 'मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' से सम्मानित किया जाना रेलवे सुरक्षा बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

शासकीय संभागीय आईटीआई एवं शासकीय आईटीआई लहार में प्रवेश का अंतिम अवसर 15 अक्टूबर तक

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



जिले के युवक-युवतियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिण्ड तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लहार में विभिन्न व्यवसायों की रिक्त सीटों पर प्रवेश का अंतिम अवसर दिनांक 15 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध है। शासकीय संभागीय आईटीआई भिण्ड में वुड वर्क टेक्नीशियन, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लंबर, सिलाई प्रौद्योगिकी, वेल्डर एवं शासकीय आईटीआई लहार में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर (हिंदी), ड्रोन टेक्नीशियन आदि व्यवसायों में प्रवेश लिया जा सकता है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग के लिए विभागीय पोर्टल पर जाएं। ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर शासकीय संभागीय आईटीआई भिण्ड में संपर्क कर मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा रेलवे, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर नियंत्रण हेतु Artificial Intelligence आधारित मानव रहित ई-चेकगेट व्यवस्था लागू

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से Artificial Intelligence (AI) आधारित मानव रहित 'ई-चेकगेट' लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों पर अनिवार्य किया गया है। सभी खनिज का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों/परिवहनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि अपने वाहनों पर ऋण ऋड्डद्द अनिवार्य रूप से स्थापित करना सुनिश्चित करें। स्थापितरख-रखाव वाहन स्वामी द्वारा किया जावेगा, यह क्षतिग्रस्त होने पर परिवहन प्रतिबंधित कर ई-खनिज पोर्टल में वाहन का पंजीयन निरस्त किया जावेगा। RF Tag क्रय करने हेतु आवश्यक शुल्क का भुगतान संबंधित वाहन स्वामी को ही करना होगा। RF Tag क्रय करने की प्रक्रिया के लिए e-checkgate पोर्टल पर जाएं। विकल्प पर क्लिक करें। वाहन विवरण दर्ज करते हुए Add Vehicle विकल्प का चयन करें। बिलिंग से संबंधित जानकारी भरें। अतः खनिज का परिवहन करने वाले वाहन मालिक/परिवहनकर्ता उपरोक्त कार्य 25 दिवस में करना सुनिश्चित करें।

रतलाम पुलिस की कार्रवाई, 20 लाख रुपये होल्ड; दो आरोपी हैदराबाद और एक कर्नाटक से गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 55 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

एक सत बुलेटिन, रतलाम/इंदौर

डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में रतलाम पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को मुंबई पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर कुवैत में मोटर पार्ट्स का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को डराया और रकम विभिन्न बैंक खातों में जमा करा ली। पुलिस ने ठगी की रकम में से करीब 20 लाख रुपये होल्ड कराए हैं। पुलिस के अनुसार, रतलाम में रह रहे फरियादी को 15 सितंबर को फोन कर खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने मोबाइल नंबर के कथित आपराधिक इस्तेमाल और पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े व्यक्ति से बातचीत का आरोप लगाया। इसके बाद एफआईआर और जांच का भय दिखाकर आधार कार्ड व पैन कार्ड की जानकारी हासिल की गई। अगले दिन आरोपियों ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने व्यक्तियों से बात कराई। हथियारों की तस्वीरें और सुप्रीम कोर्ट के लेटरहेड पर तैयार फर्जी दस्तावेज भेजकर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया। जांच और सत्यापन के नाम पर रकम जमा कराने तथा बाद में लौटाने का झांसा देकर आरटीजीएस के माध्यम से 55 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। शिकायत पर माणकचौक थाने में प्रकरण दर्ज कर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बैंक खातों, लेन-देन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में 35 लाख रुपये एक बैंक खाते में पहुंचने का पता चला।



बैंकिंग विवरण के आधार पर एक आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में धारवाड़ (कर्नाटक) से दूसरा आरोपी पकड़ा गया। दूसरे बैंक खाते में पांच लाख रुपये स्थानांतरित होने के मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये होल्ड कराए हैं। शेष रकम के लेन-देन और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई वैध सरकारी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही जांच या सत्यापन के नाम पर बैंक खाते में रकम जमा कराने को कहती है। ऐसे कॉल आने पर व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।ऐसे दिया वारदात को अंजाम मिली जानकारी के मुताबिक, ठगों ने पीड़ित को फोन कर खुद को सीबीआई और कस्टम्स विभाग का अधिकारी बताया। आरोपियों ने पीड़ित को डराते हुए कहा कि उनके नाम से भेजे गए एक पार्सल में संदिग्ध सामान और ड्रग्स पाए गए हैं। इसके बाद, कानूनी कार्रवाई और जेल जाने का भय दिखाकर पीड़ित को कई घंटों तक 'डिजिटल अरेस्ट' (वीडियो कॉल पर नजर रखना) रखा गया। मामले को रफा-दफा करने और जांच के नाम पर आरोपियों ने पीड़ित को बैंक खातों की गोपनीय जानकारी साझा न करने की बात कही और उनसे अलग-अलग खातों में कुल 55 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। जब पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही साइबर टीम ने तकनीकी सर्विलांस और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने गिरोह का सुराग लगाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दो दिवसीय दौरे पर आइजॉल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 320 करोड़ की 10 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर बनेगा विकसित भारत 2047 का प्रमुख ग्रोथ इंजन : ज्योतिरादित्य सिंधिया

■ एक सत बुलेटिन, **आइजॉल/गुवाहाटी।**





केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर मिजोरम की राजधानी आइजॉल पहुंचे। इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। सिंधिया के दौरे के दौरान मिजोरम को लगभग ?320 करोड़ की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन भी करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुदृढ़ करना तथा क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को साकार करना है। आइजॉल पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मिजोरम के साथ उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत पुराना संबंध रहा है और यहां दोबारा आना उनके लिए सुखद है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को देश की 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर के आठों राज्य विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सिंधिया ने कहा कि उनके इस दौरे का स्पष्ट उद्देश्य विकास परियोजनाओं को गति देना, आधारभूत संरचना का विस्तार करना और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना है। राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर जोर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वर्ष 2025 में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लगभग ?4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों में मिजोरम के लिए भी महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता और किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से निवेश की संभावनाओं को साकार करने और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 3.0 के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा स्थानीय उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। ऋण सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के नए अवसर विकसित होंगे। विकास और प्रगति के स्पष्ट एजेंडे के साथ मिजोरम पहुंचे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोहराया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के स्पष्ट एजेंडे के साथ मिजोरम पहुंचे हैं। इस दौरे के माध्यम से राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, विकास परियोजनाओं को गति देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। यह दौरा मिजोरम की विकास यात्रा को गति देने के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने और विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प में क्षेत्र की भागीदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लायंस क्लब का गरबा महोत्सव आज, धनुश्री चौहान होंगी गेस्ट



भोपाल। लायंस क्लब इंटरनेशनल 3233-जी2 के अंतर्गत लायंस ऑफ भोपाल द्वारा मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को गरबा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लालघाटी स्थित लैंडमार्क गार्डन में आयोजित गरबा महोत्सव में फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश 2026 धनुश्री चौहान सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शामिल होंगी। लायंस ऑफ भोपाल के समन्वयक लायन हरिओम जटिया ने बताया कि समारोह में लायंस क्लब के 38 क्लबों के सदस्य सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ आर्ट स्टूडियो के 300 प्रशिक्षित गरबा कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ होगा। इस अवसर पर लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन महेश मालवीय तथा लायंस क्लब के को-कॉर्डिनेटर एमजेएफ लायन मुनेन्द्र वैद्य विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम रात 8 बजे शुरू होगा।

रेलकर्मियों और संविदा कर्मचारियों को चार प्रकार के कचरे के पृथक्करण की दी जा रही जानकारी

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल में विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा देने, कार्यालयीन एवं रेलवे परिसरों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 11 एवं 12 अक्टूबर 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों, डिपो, शेड एवं कार्यालयों में रेलकर्मियों तथा संविदा कर्मचारियों को चार प्रकार के कचरे के पृथक्करण के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। संबंधित डिपो, शेड एवं कार्यालयों के यूनिट प्रभारियों द्वारा अपने-अपने कार्यस्थलों पर जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। अभियान के दौरान कर्मचारियों को गीले कचरे, सूखे कचरे, सैनिटरी अपशिष्ट तथा विशेष देखभाल वाले अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्र करने, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उनका निस्तारण करने तथा कार्यस्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के महत्व की जानकारी दी जा रही है। प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेष अभियान 6.0 का उद्देश्य रेलवे परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा कर्मचारियों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इस पहल के माध्यम से रेलवे स्टेशनों, डिपो, शेड एवं कार्यालयों में स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्यस्थल बनाए रखने के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

संभागायुक्त कार्यालय की समीक्षा बैठक, लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें: संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए है कि कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था को मजबूत बनाएं और ई-फाइल्स पर ही प्रकरण भिजवाएं। संभागायुक्त श्री शर्मा ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में संभागायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा और सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त श्री शर्मा ने लंबित भूमि आवंटन प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण, लोकसेवा गारंटी अधिनियम प्रकरण, आयुक्त कार्यालय की विकास शाखा में लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। भोपाल जिले के लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने से उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त श्री शर्मा ने लंबित विभागीय जांच के प्रकरणों और गूगल शीट पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी निर्देश दिए। सीहोर जिले में गूगल शीट पर प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक पाई गई। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि न्यायालयीन प्रकरणों में समय से जबाबदावा प्रस्तुत करना तथा दिए गए निर्णेयों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत होने के उपरांत प्रशासनिक अनुशासन एवं नीतिगत नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद कोठी (जिला सतना) श्री संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत चालान के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) संभाग रीवा द्वारा श्री संजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) तथा 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रीवा के समक्ष आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 दर्ज किया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान श्री सिंह का मुख्यालय 'कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संभाग रीवा' नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



दो दिवसीय नशा मुक्ति चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर में 90 रोगियों को मिला उपचार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



मद्य निषेध सप्ताह के उपलक्ष्य में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल में दो दिवसीय नशा मुक्ति चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 90 रोगियों को नशा मुक्ति संबंधी विशेष चिकित्सा एवं आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। शिविर के सफल आयोजन से पूर्व महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आसपास के क्षेत्रों एवं बस्तियों जैसे नेहरू नगर, राहुल नगर, पंचशील नगर, शबरी नगर एवं सर्वधर्म कॉलोनी आदि इलाकों में घर-घर जाकर शिविर के संबंध में व्यापक जन- जागरूकता फैलाई गई तथा अधिक से अधिक लोगों तक शिविर की जानकारी पहुँचाई गई। शिविर के दौरान विशेषज्ञों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों, इसके कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं तथा नशा छोड़ने के विभिन्न प्रभावी चिकित्सकीय उपायों के संबंध में रोगियों को जागरूक किया गया। ओपीडी में आए रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर उन्हें आवश्यकतानुसार आयुर्वेद आधारित चिकित्सा, परामर्श एवं पुनर्वास संबंधी उपचार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अगद तंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. उर्मिला शुक्ला के संयोजन एवं मार्गदर्शन में विशेष जन-जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में डॉ. भूषण सिंह द्वारा नशा मुक्ति एवं जन-जागरूकता विषय पर एक अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरक अवेयरनेस लेक्चर प्रस्तुत किया गया।

आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें बिलकुल लापरवाही न हो. अधिकारी विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय, नियमित समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य संस्कृति को अपनाएं।राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें, कार्य में कोई लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय में वीसी के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा उपस्थित थे। संभागायुक्त श्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा प्रबंधन में दर्ज प्रकरणों के समय - सीमा बाहर एवं 50 दिवस से अधिक की शिकायतों एवं शिविर वार दर्ज शिकायतों का निराकरण करें। प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन नियत समय में दर्ज करवाएं। संभागायुक्त श्री शर्मा ने बैठक में उपायुक्त राजस्व को संभाग के सभी जिलों में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के समय - सीमा बाहर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए संभाग के सभी जिलों में फोर्स क्लोज शिकायतों के हितग्राहियों से चर्चा कर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए. संभागायुक्त श्री शर्मा ने बैठक में सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट, कार्यालयीन काम-काज में पारदर्शिता, समयबद्ध और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने एवं संभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेंड कार्य प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया।

'सशक्त मां-सशक्त भारत' की थीम पर झाबुआ में बनी भव्य ह्यूमन रंगोली

3500 बेटियों ने मिलकर उकेरी मां की ममता

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



आमतौर पर रंगोली रंगों से सजती है, लेकिन झाबुआ में नजारा कुछ ऐसा था कि रंगों की जगह इंसान ही रंग बन गए। करीब 3500 स्कूली छात्राओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मां की गोद में दुलार पाते बच्चे की ऐसी आकर्षक मानव रंगोली रची कि मातृत्व का भाव मैदान में साकार हो उठा। पीजी कॉलेज ग्राउंड में सजी इस अनूठी रंगोली ने देखने वालों को चौंकाया भी और मां-बच्चे के रिश्ते की आत्मीयता का अहसास भी कराया। 'सेवा के रंग राष्ट्र के संग' कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सामूहिक प्रस्तुति का संदेश स्पष्ट था–मां सशक्त होगी, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 'सशक्त मां-सशक्त भारत' की थीम पर हजारों प्रतिभागियों ने एक साथ निर्धारित आकार में बैठकर मां और बच्चे की आकृति बनायी। इतने बड़े समूह का एक साथ, एक ही डिजाइन में ढलना अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहा। जनजातीय बहुल झाबुआ में यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, सामूहिक एकता और जनभागीदारी की प्रभावशाली मिसाल बना। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मानव रंगोली के लिए चयनित प्रदेश के छह जिलों में झाबुआ का शामिल होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि मां परिवार की आधारशिला है। शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक मां बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ सशक्त समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों का एक साथ मानव रंगोली बनाना अनुशासन, टीमवर्क और बेहतर समन्वय का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दर्शाता है कि सामूहिक सहभागिता से बड़े उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अमित शर्मा** द्वारा प्रकाशन स्थल बी-9 विवेक विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 से प्रकाशित एवं सर्वोदय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार केनरा बैंक के पास ग्वालियर (म.प्र.)-474001 से मुद्रित। स्थानीय संपादक राजीव शुक्ल* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI - MPHIN/2019/79098/ E-mail: EKSATBULLETIN@GMAIL.COM, WWW.EKSATBULLETIN.IN, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088